AMAR UJALA MY CITY PAGE 5

अब पांच साल में परास्नातक के साथ पीएचडी की भी डिग्री

लखनऊ विश्वविद्यालय सत्र 2021-22 से शुरू करेगा इंटीग्रेटेड पीएचडी पाठ्यक्रम

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 2021-22 से इंटीग्रेटेड पीएचडी की व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इसमें विवि परास्नातक पर दाखिला लेगा। इसकी डिग्री पूरी करने पर विद्यार्थी को पीएचडी में प्रवेश मिल जाएगा। फिर थीसिस जमा करने के बाद उसे डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाएगी।

प्रवक्ता डॉ. दुर्गेश श्रीवास्तव के अनुसार, कई विद्यार्थी स्नातक स्तर से ही शोध के लिए गंभीर होते हैं। इन्हें परास्नातक स्तर से ही शोध के लिए तैयार किया जाना चाहिए। इसके लिए लविवि ने इंटीग्रेटेड पीएचडी की शुरुआत करने का फैसला किया है। इस पाठ्यक्रम में दाखिला लेने पर विद्यार्थी को पीजी के साथ पीएचडी की उपाधि भी मिलेगी। कोर्स की अवधि भी काफी कम रहेगी। सिर्फ पांच साल में परास्नातक और पीएचडी दोनों डिग्री मिल जाएंगी। इंटीग्रेटेड पीएचडी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए विद्यार्थी को स्नातक स्तर पर कम से कम 60 फीसदी अंक लाना जरूरी होगा। प्रवेश परीक्षा, एकेडमिक इंडेक्स और साक्षात्कार के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। प्रवेश परीक्षा और एकेडमिक इंडेक्स का भाग 40-40 फीसदी और 20 फीसदी नंबर साक्षात्कार के आधार पर दिए जाएंगे।

परास्नातक में 55 फीसदी नंबर अनिवार्य

पीएचडी पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए केवल वही विद्यार्थी पात्र होंगे, जो परास्नातक स्तर पर कम से कम 55 फीसदी नंबर या फिर 5.5 सीजीपीए हासिल करेंगे। परास्नातक कोर्स में विद्यार्थी को दो साल में 96 क्रेडिट भी पूरे करने होंगे। जो विद्यार्थी इन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे उन्हें परास्नातक कोर्स की डिग्री दे दी जाएगी। शोध का टॉपिक आवंटित होने के बाद विद्यार्थी को न्यूनतम दो साल में थीसिस जमा करनी होगी। विद्यार्थी को कोर्स की अवधि के दौरान 75 फीसदी उपस्थिति रखनी होगी।

50 हजार रुपये की मदद का भी प्रस्ताव

विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए थीसिस जमा करने पर 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव भी है। यह राशि उन विद्यार्थियों को मिलेगी, जिन्हें अन्य स्रोत से कोई स्कॉलरशिप न मिल रही हो। पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा पास करने पर पूरे परास्नातक पाठ्यक्रम की फीस वापस करने का प्रस्ताव है।

विभाग में एक बार में अधिकतम पांच दाखिले

इंटीग्रेटेड पीएचडी ऑर्डिनेंस के अनुसार, इंटीग्रेटेड पीएचडी की सीट केवल उन्हीं विभागों में होगी जहां शिक्षकों के कम से कम 10 पद हों। इसके साथ ही एक विभाग में इंटीग्रेटेड पीएचडी की अधिकतम पांच सीट की बाध्यता होगी। इस तरह से पीएचडी गाइड के लिए मारामारी की स्थिति नहीं होगी।

“ शोध को दिया जा रहा बढ़ावा

लविवि शोध को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। इसके तहत इंटीग्रेटेड पीएचडी पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। नए सत्र से इसके दाखिले शुरू हो जाएंगे। -डॉ. दुर्गेश श्रीवास्तव, प्रवक्ता लविवि

i-NEXT PAGE 2

प्रदेश में कुपोषण का सच बताएगा एलयू

LUCKNOW (5 Feb, inext):
लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रदेश में कुपोषण की समस्या के पीड़ित महिलाओं और बच्चों पर बेस लाइन सर्वे करेगा. इस सर्वे से पता लगाया जाएगा कि प्रदेश में कुपोषण के कारण क्या हैं और इसे दूर करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाने चाहिए. नीति आयोग ने इसके लिए पूरा प्रोजेक्ट एलयू को दिया है. यूनिवर्सिटी के सांख्यिकी विभाग को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत यह प्रोजेक्ट दिया गया है. सर्वे में सहयोग के लिए विभाग और नागपुर की संस्था राम भाऊ महाल्गी प्रबोधिनी के साथ एमओयू भी किया गया है.

CONCEPT PIC

लखनऊ यूनिवर्सिटी को मिली कुपोषण के कारणों का पता लगाने की जिम्मेदारी

यूनिवर्सिटी प्रदेश के 15 जिलों के एक ब्लॉक के तीन ग्राम पंचायतों में करेगी रैपिड सर्वे

100 कुपोषित जिले देश में किए गए चिंहित

15 कुपोषित जिले प्रदेश के लिस्ट में

“ विभाग ने प्रदेश के 15 जिलों में हाउस होल्ड मैपिंग और सूची बनाने का काम शुरू कर दिया है. इसमें प्रोजेक्ट फेलो और रिसर्च स्कालर सहयोग करेंगे.

प्रो. शीला मिश्रा, सांख्यकीय विभाग, एलयू

प्रदेश के 15 जिले शामिल

नेशनल फैमिली हेल्थ के पांचवें सर्वे में देश में कुपोषण से ग्रसित 100 जिले चिंहित किए गए हैं. इसमें उत्तर प्रदेश के 15 जिले शामिल हैं. नीति आयोग कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न स्टेट को इसके लिए प्रोजेक्ट देती है. इसी कड़ी में यूपी के जिलों में कुपोषण का पता लगाने के लिए यह प्रोजेक्ट मिला हैं. जिसकी जिम्मेदारी सांख्यिकी विभाग की प्रो. शीला मिश्रा को मिली है, उन्हें ही इस प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया है.

इस तरह होगा काम

प्रो. शीला मिश्रा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत हम रैंडम बेस लाइन सर्वे से पहले हाउस होल्ड मैपिंग करेंगे. जिससे हमें इन जिलों में कुपोषण के ग्रसित जगहों की सही जानकारी मिले. इसके बाद विभाग एनजीओ के माध्यम से 15 जिले के एक ब्लाक के तीन ग्राम पंचायतों में रैंडम सर्वे करेगा. 15 से 50 आयु वर्ग महिलाओं, छोटे बच्चों और स्तर पान कराने वाली महिलाओं की पोषण की स्थिति का आंकलन किया जाएगा. उनके खान-पान, सेनेटाइजेशन की आदत, पानी, स्वच्छता से लेकर परिवार की आय सहित कई चीजें देखी जाएंगी. छह माह तक बेस लाइन सर्वे चलेगा.

TOI PAGE 4

Disabled candidates have 21 days to apply for LU teaching posts

Mohita.Tewari@timesgroup.com

Lucknow: Lucknow University will give 21 days to physically handicapped (PH) candidates to apply for the teaching posts reserved for them. A committee formed for providing PH reservation submitted its report on Friday.

The committee in its report said there are six posts, three for assistant professor, two for associate professor, and one for professor reserved under the category.

Posts in the departments of botany, history, chemistry and Arabic are likely to come under reservations.

"We have provided reservation in a manner that no injustice is done to anyone. This is not random pick and choose of the department for providing reservation. We have strictly followed the UGC rostering and government reservation rules," said vice-chancellor Prof Alok Kumar Rai.

He added, "We will open the recruitment portal for candidates to apply for the posts and also to get a refund for the post they had applied for earlier and which has gone under the PH category."

Interviews to be recorded

LU will record interviews of candidates during the recruitment process to ensure transparency and to present proof if required by higher authorities later. Besides, the V-C will also assign marks out of 100 just like other experts and HoD of the selection committee. TNN

In September, LU issued an ad inviting applications for 180 vacant teaching posts without provision for horizontal reservation to PH candidates. According to LU officials, the error occurred because there was no specific mention of such quota in government guidelines for appointments.

Recently, the office of the commissioner of persons with disabilities had asked LU to make provision for reservation of disabled candidates in recruitment process. Subsequently, a committee was formed to recommend modalities for introducing the PH quota on 180 posts without disturbing the ongoing drive.

JAGRAN CITY PAGE III

चिकन और जरदोजी कारीगरी के साथ फ्यूजन वर्क भी जानेंगे छात्र

जासं, लखनऊ : अभी तक कपड़ों पर चिकन और जरदोजी का काम तो बहुत देखा गया है। अब छात्र-छात्राएं फ्यूजन वर्क (चिकन वर्क और पेंटिंग मिलाकर किया जाने वाला काम) के बारे में भी जानेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय की भाऊराव देवरस पीठ जल्द ही ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत करेगी। ट्रेनिंग के दौरान एक्सपर्ट लखनऊ के चिकन, जरदोजी से लेकर बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी, मंजुषा पेंटिंग, महाराष्ट्र की वर्ली और तामिलनाडु की टाडा पेंटिंग व डिजाइन के बारे में भी बताएंगे, जिससे छात्र स्टार्टअप भी शुरू कर सकेंगे।

भाऊराव देवरस पीठ के निदेशक प्रो. सोमेश कुमार शुक्ला ने बताया कि लखनऊ की चिकन कारीगरी और जरदोजी का काम हर जगह मशहूर है, लेकिन अभी तक फ्यूजन वर्क को मिलाकर चिकन पर काम नहीं हुआ

है। 'फ्यूजन वर्क फार चिकन एवं जरदोजी' विषय पर होने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक्सपर्ट इसकी बारीकियां, इससे शुरू होने वाले स्टार्टअप और स्कीम आदि के बारे में जानकारी देंगे। कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने इस आयोजन की सहमति दे दी है। जल्द ही इसकी तिथियां घोषित की जाएंगी। स्माल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के साथ भाऊराव देवरस पीठ का एमओयू है। उनके सहयोग से चार दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। प्रो. सोमेश कुमार शुक्ला के मुताबिक चिकन, जरदोजी में फ्यूजन कान्सेप्ट, एम्ब्रायडरी का प्रयोग, उसकी डिजाइन, मार्केटिंग से लेकर बंगाल का काथा और कर्नाटक के कसूती वर्क से भी विशेषज्ञ विस्तार से बताएंगे। उनका कहना है कि अभी तक भारत में चिकन कारीगरी पर फ्यूजन वर्क का प्रयोग भारत में नहीं हुआ है, इसलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसे शामिल किया गया।

लविवि करेगा कुपोषण से ग्रसित परिवारों का बेस लाइन सर्वे : लखनऊ विश्वविद्यालय कुपोषण की समस्या से ग्रसित महिलाओं और बच्चों पर बेस लाइन सर्वे करेगा। इसके लिए नीति आयोग ने विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग को सेंटर आफ एक्सीलेंस के तहत यह प्रोजेक्ट दिया है। सर्वे में सहयोग के लिए विभाग और नागपुर की संस्था राम भाऊ महाल्गी प्रबोधिनी के साथ बीते दिनों एमओयू हो चुका है। अब विभाग ने प्रदेश के 15 जिलों में हाउस होल्ड मैपिंग और सूची बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसमें प्रोजेक्ट फेलो और रिसर्च स्कालर सहयोग करेंगे।

दरअसल, नेशनल फैमिली हेल्थ के पांचवे सर्वे में भारत में कुपोषण से ग्रसित 100 जिले चिह्नित किए हैं, इनमें 15 जिले उत्तर प्रदेश के हैं। प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर एवं सांख्यिकी विभाग की प्रो. शीला मिश्रा ने बताया कि नीति आयोग के माध्यम से चलाए जा रहे पोषण जन अभियान के लिए बेस लाइन सर्वे कराया जाएगा।

कब तक आस लगाओगी : यौन अपराध पर बेटियों की दो टूक

लविवि के डिपार्टमेंट आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत यौन अपराध : किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों को समर्थन के विषय पर दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया।

पहले दिन शुक्रवार को रंगोली, एक्सटेंपोर (भाषण) और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताएं हुईं। प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। एक्सटेंपोर प्रतियोगिता में 11 छात्र, पोस्टर मेकिंग में 10 और रंगोली मेकिंग में तीन टीमों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डा.अलका मिश्रा, सुनीता श्रीवास्तव व किरण लता डंगवाल ने परिणाम घोषित किए। भाषण प्रतियोगिता के तहत महिला सशक्तीकरण पर 'कब तक आस लगाओगी' विषय पर अपने विचार रखने वाली प्रिया त्रिपाठी विजेता रहीं। संचालन डा. रितु नारंग द्वारा किया गया।

प्रतियोगिता में पोस्टर बनाती अंजली बघेल ● जागरण